भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †3565

उत्तर देने की तारीख 20/12/2021

जनजातीय आबादी का विस्थापन

†3565. श्री अब्दुल खालेक:

श्री जयदेव गल्ला:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान विस्थापित जनजातीय संबंधी डाटा सरकार के पास है;
(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विस्थापन के क्या कारण हैं और विस्थापित लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है;
(ग) सरकार द्वारा ऐसे जनजातीय लोगों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार जनजातीय औषधियों के परंपरागत ज्ञान के लिए जनजातीय लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कोई मुआवजा प्रदान करती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग) : जहां तक भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, भूमि संबंधी मुद्दों का संबंध है; भारत सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) अधिनियममित किया है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य संविधान के तहत गठित स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं और ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करना; भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है या अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, भूमि के अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कम से कम परेशानी और प्रभावित परिवारों को ठीक और उचित मुआवजे की प्रदायगी सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), केंद्र में एक नोडल मंत्रालय है जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में निगरानी की भूमिका निभाता है। भूमि और उसका प्रबंधन, भारत के संविधान [सातवीं अनुसूची - सूची ii (राज्य सूची) - प्रविष्टि संख्या (18)] के तहत प्रदान किए गए राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा नीचे दी गई है:

(i) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 48 के तहत, डीओएलआर के आदेश संख्या 26011/04/2007-एलआरडी दिनांक 2 मार्च, 2015 के अंतर्गत डीओएलआर में पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन तथा आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित योजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विस्थापन की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपायों के द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 41 और 42 के तहत उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और पद्धतियों का भी उल्लेख है।

(iii). आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की पहली अनुसूची में भूमि मालिकों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में, प्रभावित सभी परिवारों (दोनों भूमि के मालिक और वे परिवार जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित भूमि पर निर्भर है) के लिए, पहली अनुसूची में प्रदान किए गए मूल तत्वों के अतिरिक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए मूल तत्वों का प्रावधान है। इसी तरह, तीसरी अनुसूची में पुनर्वासन के क्षेत्र में एक उचित रूप से निर्वाह योग्य और नियोजित बंदोबस्त के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा जनजातीय लोगों के विस्थापन के मुद्दों का समाधान करने के लिए, जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य संवैधानिक और कानूनी प्रावधान, जो पहले से ही मौजूद हैं, निम्नानुसार हैं:-

i. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, की धारा 4 (5) में कहा गया है कि जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासी के किसी भी वनवासी सदस्य को मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक, उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा।

ii. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों या विकास परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले और ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ।

iii. भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के जोखिम से बचाव के लिए अनुसूची - V के तहत संवैधानिक प्रावधान सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को, जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम या प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि का आवंटन विनियमित करने का अधिकार है।

iv. "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों के मुकदमों के प्रावधान और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास की राहत और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए लाया गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना या किसी भूमि या परिसर या पानी या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के भोग में हस्तक्षेप करना या फसलों को नष्ट करना या उनसे उपज ले जाना अपराध की श्रेणी में आता है, अत्याचार के और उक्त अधिनियम के तहत दंड के अधीन हैं।

(घ) : जैविक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान स्वयं संसाधन का एक अमूर्त घटक है। पारंपरिक ज्ञान में उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के लिए लीड प्रदान करके व्यावसायिक लाभों में बदलने की क्षमता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए, चाहे वह भारत में या भारत से बाहर किसी भी नाम से जाना जाता हो, भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर भारत में या उसके बाहर किसी भी शोध या जानकारी के आधार पर ऐसा आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं करेगा।

*****